मेसर्स श्री रैम मिल्स लिमिटेड।

वी.

मेसर्स यूटिलिटी प्रीमिसेस (पी) लिमिटेड।

21 मार्च, 2007

[एच. के. सेमा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 11 (6)-पक्षों के बीच विकास के लिए भूमि का एक क्षेत्र प्रदान करने का समझौता

एक अन्य समझौता तब हुआ जब सहमत क्षेत्र का केवल एक हिस्सा उपलब्ध कराया गया-मुआवजे के भुगतान द्वारा विवाद को निपटाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया-पीड़ित पक्ष ने एमओयू को अस्वीकार कर दिया और समझौते के तहत मध्यस्थता खंड को लागू किया।

की शुद्धता-अधिनियम के तहत आयोजित, उच्च न्यायालय केवल मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों के बीच लाइव मुद्दे के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है-मध्यस्थता न्यायाधिकरण विवाद का निर्णय लेते समय लाइव मुद्दे और सीमा के प्रश्न में जा सकता है।

अपीलार्थी-कंपनी ने अपीलार्थी के स्वामित्व वाली भूमि के विकास के लिए एक क्षेत्र प्रदान करने के लिए प्रतिवादी-कंपनी के साथ एक समझौता किया। बाद में, पक्षों के बीच एक दूसरा समझौता निष्पादित किया गया क्योंकि अपीलार्थी प्रतिवादी को सहमत क्षेत्र का केवल एक हिस्सा उपलब्ध करा सकता था। ए.

क्षतिपूर्ति राशि के लिए विवादों को निपटाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रत्यर्थी को मुआवजे की राशि का आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ। इसके बाद, प्रतिवादी ने समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया और प्राप्त राशि को वापस कर दिया। प्रत्यर्थी ने दोनों समझौतों के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान इस आधार पर किया कि अपीलार्थी पहले समझौते के अनुसार सहमत एफ. एस. आई. की पूरी सीमा को हस्तांतरित करने में विफल रहा। जब अपीलार्थी ने अपने दायित्व से इनकार किया,

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता याचिका विफल कर दी गई थी

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6)

मध्यस्थ। उच्च न्यायालय के एक नामित न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पक्षकारों के बीच कोई सजीव मुद्दा अस्तित्व में नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी ने पहले समझौते के तहत अपने दावे के हिस्से को छोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था; कि प्रत्यर्थी

279 [2007] 4 एस सी आर।

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता ज्ञापन को एकतरफा रूप से रद्द नहीं कर सकते हैं और इसके तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान नहीं कर सकते हैं।

समझौते; कि प्रत्यर्थी का दावा, यदि कोई हो, वर्जित हो गया था सीमा द्वारा; कि उच्च न्यायालय, मध्यस्थता याचिका में, पहले से ही जीवित दावे और सीमा के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष दिए गए हैं और इसलिए,

निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण करना इस न्यायालय का काम है।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि चूंकि पहले के तहत देनदारियां मुद्दा या नहीं और सीमा का मुद्दा, मध्यस्थ द्वारा तय किया जा सकता है अधिनियम की धारा 16 के तहत न्यायाधिकरण क्योंकि उच्च न्यायालय ने अंततः नहीं किया है

इस तरह के मुद्दों का फैसला किया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया:

1.1. एक मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के उनके नामित, के तहत

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) को इस बात की जांच करनी है कि क्या दावा मृत है या क्या पक्षकारों के पास पहले से ही है।

लेन-देन का समापन किया और अपनी पारस्परिक संतुष्टि दर्ज की है अधिकार और दायित्व या क्या संबंधित पक्षों ने अपने अधिकार दर्ज किए हैं

वित्तीय दावों की संतुष्टि। इसकी जाँच करते हुए, यदि पक्षकार

वित्तीय दावों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की है, कोई नहीं होगा

किसी भी शेष मुद्दे का प्रश्न। यह इस अर्थ में है कि उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या दोनों के बीच कुछ तय किया जाना बाकी है।

समझौते के संबंध में पक्षकार और क्या पक्षकार अभी भी मुद्दे पर हैं इस तरह के किसी भी मामले में। यदि मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं करते

हैं, तो उस मामले में निर्णय लें। यदि वह इस तरह के मुद्दे का पता लगाने और इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने के लिए है

1 पक्षों के बीच मुद्दा मौजूद है। यह केवल उस अर्थ में है कि निष्कर्ष पर एक जीवंत मुद्दा दिया जाता है। यह केवल यह पता लगाने के उद्देश्य से है कि क्या मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसे मुख्य न्यायाधीश को दर्ज करना होगा

इस बात से संतोष है कि पक्षों के बीच एक जीवित मुद्दा बना हुआ है। [पैरा 27]:

1.2. मुख्य न्यायाधीश को केवल अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होती है कि प्रथम ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुद्दा समय बीतने के साथ समाप्त नहीं हुआ है या समझौते के किसी भी पक्ष ने समझौते के दायरे में आने वाले मुद्दों को उठाने के लिए कानून द्वारा अनुमत समय से अधिक अपने अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले लाइव दावे के संबंध में प्रश्न को छोड़ना उचित होगा। उसे केवल अपनी संतुष्टि दर्ज करनी है कि पक्षकार अपने अधिकारों को बंद कर दिया है और मामले को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया गया है।

-4 281 श्री रैम मिल्स लिमिटेड। वी. UTILITY PREMISES (P) LTD.

इस प्रकार, जहां मुख्य न्यायाधीश एक निष्कर्ष पर आते हैं कि एक जीवित अस्तित्व मौजूद है मुद्दा, तो स्वाभाविक रूप से इस खोज में एक निष्कर्ष शामिल होगा कि संबंधित पक्षकारसभक दावा सीमिततासँ वर्जित नहि भेल अछि। जब वहाँ था

एक जीवित मुद्दा, सीमा का सवाल अपने आप हल हो जाता है। जहाँ बातचीत अभी भी चल रही थी, वहाँ शुरू करने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

सीमा अवधि। [पैरा 27 और 30] [289-ई-जी; 292-जी; 293-ए]

एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ए. एन. आर., [2005] 8 एस. सी. सी. 618 और हरि शंकर सिंघानिया और अन्य। वी. गौर हरि सिंघानिया और अन्य।, [2006] 4 एस. सी. सी. 658, संदर्भित।

1.3. इस न्यायालय के पास यह तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि क्या उत्तरदाताओं को समझौता ज्ञापन को अस्वीकार करने और मध्यस्थता की सूचना देने का अधिकार था। तथ्य यह है कि पार्टियों ने समझौता ज्ञापन बनाने के लिए चुना था, यह बताता है कि इसे कभी भी बंद नहीं माना गया था और उस अर्थ में यह अभी भी एक जीवित मुद्दा था। यह केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए होगा कि वह प्रतिवादी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रभाव का निर्णय करे। तथ्यों पर,

समझौता ज्ञापन द्वारा भी इस मुद्दे का कोई अंतिम समाधान नहीं हुआ था। यदि ऐसा था, तो पार्टियों के बीच लाइव मुद्दा था और पार्टियों के बीच उस मुद्दे पर लॉगरहेड्स थे।

[पैरा 29] [292-एफ-जी।

नथानी स्टील्स लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शंस, [1995] सप। 3 एससीसी

324, प्रतिष्ठित।

1.4. प्रत्यर्थी के दावे को मृत नहीं कहा जा सकता है सबसे पहले सीमा की चूक के कारण। मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों के बीच दावों की सीमा के सवाल पर भी विचार कर सकता है। चूंकि पक्षों के बीच मुद्दा अभी भी जीवित है, इसलिए इसे दबाने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुद्दा सीमितता से मृत हो गया है, मध्यस्थता कार्यवाही। ¡ पैरा 31] [293-एफ-जी; 294-ए-बीआई

ग्रुप चिमिक ट्यूनीशियन एसए वी। दक्षिणी पेट्रोकेमिकल उद्योग

कॉर्प. लिमिटेड, [2006] 5 एस. सी. सी. 275, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1523/2007।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के ए. ए. संख्या 123/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.8.2006 से उत्पन्न।

हरीश एन. साल्वे, श्याम दीवान, सौरभ अग्रवाल, ललित कटारिया, रूबी अपीलार्थी की ओर से सिंह आहूजा, देबमाल्या बनर्जी और माणिक करंजावाला।

के. के. वेणुगोपाल, रंजीत कुमार, सुशील के. टेकरीवाल, वेंकटेश्वर राव [2007] 4 एस. सी. आर.

282 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट उत्तरदाता के लिए अनुमोलु।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. एस. सिरपुरकर, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आदेश,

1996 (मध्यस्थों की नियुक्ति, जिसे इसके बाद संक्षिप्त में "अधिनियम" कहा जाता है, पारित किया गया श्री राम मिल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "याचिकाकर्ता" कहा जाता है) के कहने पर इस अपील में बंबई उच्च न्यायालय के नामित न्यायाधीश से पूछताछ की जाती है।

3. उक्त आदेश मुख्य रूप से दो आधारों पर लगाया गया है, पहला, कि पक्षकारों और विद्वान न्यायाधीश के बीच कोई सजीव मुद्दा अस्तित्व में नहीं था और यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि पक्षकारों के बीच

एक सजीव मुद्दा था और दूसरा यह कि दावा पक्षकारों के बीच सीमा द्वारा वर्जित हो गया था। इसके विपरीत उत्तरदाता एम/एस। यूटिलिटी प्रिमाइसेस (पी) लिमिटेड ने आदेश का समर्थन किया और बताया कि पारित आदेश के अनुसरण में न केवल मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी, बल्कि उन्होंने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करने के लिए तीसरे मध्यस्थ को भी चुना था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। वर्तमान में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

4. इसलिए यह तय किया जाना है कि क्या आदेश इसके तहत पारित किया गया है।

विशेष रूप से उपरोक्त दो आपत्तियों के मद्देनजर मध्यस्थों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 11 (6) कानून की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था है।

5. निम्नलिखित निर्विवाद तथ्यों को पहले ध्यान में रखना होगा उठाए गए प्रश्नों की ओर बढ़ना।

6. अपीलार्थी कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी है, 1956, उत्तरदाता भी। अपीलकर्ता कंपनी वर्ष 1987 में किसी समय बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (इसके बाद "एस. आई. सी. ए". के रूप में संदर्भित) के तहत एक बीमार औद्योगिक इकाई बन गई। इसे वर्ष 1994 में समाप्त करने का आदेश दिया गया था और

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) से संपर्क करने पर एक पुनर्वास योजना तैयार की गई थी जिसके तहत आई. डी. बी. आई. को योजना के तहत एक संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। परिसंपत्ति बिक्री समिति ने 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बिक्री को मंजूरी दी। फीट। अपीलकर्ता कंपनी के स्वामित्व वाले एफ. एस. आई. ने प्रत्यर्थी को रु। 21.60 करोड़ और तदनुसार बीच में एक समझौता निष्पादित किया जाने के लिए आया 27.4.1994 पर दल। यह 283 देशों के बीच एक संयुक्त विकास समझौता था।

श्री रैम मिल्स लिमिटेड। वी. UTILITY PREMISES (P) LTD. [वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे

अपीलार्थी के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में पक्षकार। समझौते के खंड 1 के अनुसार, विकास के लिए उल्लिखित क्षेत्र 86,000 वर्ग किलोमीटर के बीच था। फुट से 1.2 लाख वर्ग मीटर तक। फीट। उक्त समझौते के खंड 15 में प्रावधान है कि भूमि का मालिक, जिसमें अपीलकर्ता है, कोई बोझ या तीसरे पक्ष के अधिकार पैदा नहीं करेगा। खंड 19 द्वारा अपीलार्थी ने अतिरिक्त एफ. एस. आई. जोड़ने का बीड़ा उठाया था। खंड 22 द्वारा समझौते के अंतर्गत आने वाले पूर्ण एफ. एस. आई. के उपयोग के लिए अवधि निर्धारित की गई थी। खंड 24 पक्षकारों के बीच विवाद, यदि कोई हो, को हल करने के लिए मध्यस्थता खंड था। कवर की

गई संपत्ति का वर्णन उक्त समझौते की तीसरी अनुसूची में किया गया था जिसमें 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर का उल्लेख है। फीट। एफ. एस. आई.

7. इस समझौते के बाद एक दूसरा समझौता लागू किया गया। 18.7.1994 पर पार्टियों के बीच। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि इसमें अपीलकर्ता केवल 86,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध करा सका था। फीट। एफ. एस. आई. इस दूसरे समझौते के तहत अपीलार्थी द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि आगे की भूमि 2500 वर्ग किलोमीटर होगी। एमटीआरएस। प्रत्यर्थी द्वारा विकसित किए जाने की अनुमति दी जाएगी। उक्त 2500 वर्ग कि. मी. एमटीआरएस। बॉम्बे नगर निगम द्वारा भूमि आरक्षित की गई थी नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय और खेल का मैदान। तथापि, इसमें अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की कीमत पर उक्त आरक्षण को अपीलार्थी की किसी अन्य संपत्ति में स्थानांतरित करने का बीड़ा उठाया। इस समझौते में भी खंड संख्या.10 के माध्यम से एक मध्यस्थता खंड था।

8. 9.11.1994 पर अपीलार्थी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था और इसमें प्रतिवादी के साथ एक भूपेंद्र कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड जिसमें दिनांकित 27.4.1994 और 18.7.1994 समझौते के तहत अपीलार्थी के पूरे ब्याज का 50 प्रतिशत हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

9. 22.6.1996 पर 18.7.1994 दिनांकित समझौते को पारस्परिक रूप से रद्द कर दिया गया था सहमति क्योंकि पक्ष स्थानांतरण की लागत

पर सहमत होने में असमर्थ थे आरक्षण जिस पर दिनांकित 18.7.1994 समझौते में सहमति हुई थी। यह था, इसलिए, खंड 5 के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई कि प्रतिवादी और तीसरे पक्ष, यानी, भूपेंद्र कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड, को अपीलार्थी से संबंधित उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या दावा नहीं होगा और अधिक विशेष रूप से पहली अनुसूची में वर्णित, 86725 वर्ग कि. मी. को छोड़कर। फीट। एफ. एस. आई.

10. 28.6.1996 पर यहाँ उत्तरदाता ने एक कार्य सौंपा 86725 वर्ग किलोमीटर के एफ. एस. 1 वाले क्षेत्र में फ्लैट बनाने के लिए अंसल आवास और निर्माण के साथ समझौता। फीट।

11. 4.5.2001 पर प्रतिवादी ने धारा 284 के तहत एक याचिका दायर की थी।

[2007] 4 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 2500 वर्ग कि. मी. के संबंध में प्राप्तकर्ता की निषेधाज्ञा और नियुक्ति की मांग करने वाले अधिनियम का। एमटीआरएस। भूमि से। हालाँकि, इसे उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह क्षेत्र दिनांकित 18.7.1994 समझौते के तहत शामिल था और इसे दिनांकित 22.6.1996 समझौते द्वारा रद्द कर दिया गया था और

इसलिए, आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। इस आदेश के खिलाफ अपील भी आदेश के माध्यम से विफल रही। दिनांकित 3.6.2002।

12. 12.9.2001 प्रत्यर्थी और एक संतोष सिंह बागला जो थे

प्रत्यर्थी कंपनी के प्रवर्तक ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष आवेदन दायर किया इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी के प्रवर्तक कदाचार के दोषी थे और इसलिए उन कृत्यों की जांच की जानी चाहिए। दूसरा यह प्रार्थना की गई थी कि अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल को हटा दिया जाए। तीसरा यह प्रार्थना की गई थी कि अपीलार्थी को भूमि बेचने या हस्तांतरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए। ए. ए. आई. एफ. आर. द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था और पक्षों को एक उपयुक्त मंच के समक्ष विवादों का निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया था। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा एएआईएफआर के समक्ष एक विशिष्ट बयान दिया गया था कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर की बिक्री। फीट। आवेदन का विषय नहीं था क्योंकि उपयुक्त मंच के समक्ष अलग कार्यवाही पर विचार किया जा रहा था।

13. 11.6.2002 पर प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता का आह्वान करते हुए एक नोटिस दिया दिनांकित 27.4.1994 और 18.7.1994 समझौतों के तहत खंड इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने एफ. एस. आई. को 86725 वर्ग

किलोमीटर से आगे स्थानांतरित करने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया था। फीट।

हालांकि यह 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर का एफ. एस. आई. उपलब्ध कराने के लिए बाध्य था। फीट। उत्तरदाताओं के लिए।

14. प्रतिवादी और श्री संतोष सिंह बागला ने एक रिट याचिका दायर की 26.7.2004 पर दिल्ली उच्च न्यायालय में। जिसके तहत उन्होंने एएआईएफआर द्वारा दिनांकित 12.9.2001 द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। हालाँकि उत्तरदाताओं ने ए. ए. आई. एफ. आर. के समक्ष अपनी अपील में दावा किया था कि 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर की बिक्री की गई थी। फीट। एफ. एस. आई. का मामला उस आवेदन का विषय नहीं था, फिर भी रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि अपीलार्थी को उनके पास बचे अतिरिक्त एफ. एस. आई. को स्थानांतरित करने से रोका जाना चाहिए। इसके बाद अपीलार्थी के वकील द्वारा एक वचन दिया गया कि अपीलार्थी उस संपत्ति को नहीं बेचेगा जो दिनांकित 27.4.1994 समझौते में शामिल थी।

15. 6.8.2004 पर अपीलार्थी कवर की गई संपत्ति को गिरवी रखने के लिए सहमत हो गया आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल.

एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड. एफ. एस. के पक्ष में आई. एल. एंड

16. 15.10.2004 पर अपीलकर्ता कंपनी को एस. आई. सी. ए. से रिहा कर दिया गया था क्योंकि यह व्यवहार्य हो गया।

श्री रैम मिल्स लिमिटेड। वी. UTILITY PREMISES (P) LTD. [वी. एस. सिरपुरकर, जे. 285

17. इस समय 19.1.2005 पर एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों को निपटाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

जिसमें स्वाभाविक रूप से 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के हस्तांतरण का मुद्दा शामिल था। फीट। एफ. एस. आई. उसी के तहत प्रत्यर्थी एक करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को पहले ही एक लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था। अपीलार्थी दिनांकित 27.4.1994 और 22.6.1996 समझौते के अनुसार आवश्यक परिवहन विलेख को निष्पादित करने के लिए भी सहमत

हुआ, जिससे प्रतिवादी के दावे को 86725 वर्ग किलोमीटर तक सीमित करने की मांग की गई। फीट। एफ. एस. आई.

18. यह समझौता ज्ञापन प्रत्यर्थी द्वारा 8.3.2005 पर रद्द कर दिया गया था और उत्तरदाता ने रुपये की राशि वापस कर दी। 10 लाख।

19. प्रत्यर्थी ने 27.4.1994 और 18.7.1994 दिनांकित समझौतों के तहत 24.5.2005 दिनांकित नोटिस द्वारा मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। उक्त नोटिस का जवाब अपीलार्थी ने अपने दायित्व से इनकार करते हुए दिनांक आई. डी. 1 के जवाब के माध्यम से दिया था और इसके परिणामस्वरूप श्री एस. सी. अग्रवाल को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आई. डी. 2 पर एक मध्यस्थता याचिका दायर की गई थी। यह वह आवेदन है जिसका निपटारा विद्वान न्यायाधीश द्वारा 11.8.2006 पर किया गया था जो अपीलार्थी के कहने पर हमारे समक्ष वर्तमान कार्यवाही का विषय है।

20. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री साल्वे मूल रूप से दो बिंदु उठाए गए, वे थे

(i) कि पक्षों के बीच कोई जीवित मुद्दा नहीं बचा था और विवाद समाप्त हो गया था; और

(ii) कि प्रतिवादी का दावा, यदि कोई हो, तो सीमा द्वारा वर्जित हो गया था। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान वकील ने बड़ी मेहनत से हमें पूरे रिकॉर्ड में ले गए।

21. संक्षेप में कहा गया कि विद्वान वकील का तर्क है कि वहाँ है विशेष रूप से 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के संबंध में पक्षों के बीच कोई सजीव मुद्दा नहीं बचा है। फीट। एफ. एस. आई. विद्वान वकील सबसे पहले बताते हैं कि 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर का विषय। फीट। दिनांक 1 के समझौते के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एफ. एस. आई. का अंत में दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 2 के समझौता ज्ञापन द्वारा एक सभ्य अंतिम संस्कार किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी ने विशेष रूप से अपने दावे को केवल 86725 वर्ग किलोमीटर तक सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी। फीट। दिनांकित 27.4.1994 समझौते के तहत कवर किए गए एफ. एस. आई. का। वह बताते हैं कि उस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में न केवल प्रत्यर्थी ने कुल सहमत राशि में से Rs.10 लाख के मसौदे को स्वीकार किया। 1. 20 करोड़ लेकिन उसे भुनाने के लिए भी आगे बढ़े। विद्वान वकील बताते हैं कि एक पल में सोचा कि प्रतिवादी उक्त समझौते को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा और उसके बाद 24.5.2005 पर एक मध्यस्थता नोटिस देने के लिए आगे बढ़ा। विद्वान परामर्शदाता, [2007] 4 एस. सी. आर. 286 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, यह इंगित करता है कि सबसे पहले यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं को दिनांकित 27.4.1994 समझौते के तहत कोई अधिकार था और यदि ऐसा कोई अधिकार था, तो उन्हें दिनांकित 19.1.2005 के समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह विशेष रूप से 86725 वर्ग किलोमीटर के दावे को छोड़कर शेष दावे को छोड़ने के लिए सहमत हुआ था। फीट। एफ. एस. आई. और अपीलार्थी को 86725 वर्ग किलोमीटर के दावे के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। फीट। एफ. एस. आई. और यह हमेशा दिनांकित 27.4.1994 समझौते के संदर्भ में इसे व्यक्त करने के लिए तैयार रहेगा। विद्वान वकील का तर्क है कि 19.1.2005 दिनांकित समझौता ज्ञापन के बारे में दूसरा विचार करने पर प्रतिवादी को अपनी देनदारियों से बाहर निकलने और 27.4.1994 दिनांकित समझौते पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो एक पुराना समझौता बन गया था। अगर कोई है तो अधिकार, वे अधिकार दिनांक 19 के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में होंगेः 1.2005. इसलिए, यह इंगित किया जाता है कि पार्टियों के बीच कोई जीवित मुद्दा नहीं बचा है, विशेष रूप से 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर के संबंध में। फीट। एफ. एस. आई. जिसमें से 86725 वर्ग किलोमीटर है। फीट। एफ. एस. आई. को पहले ही प्रतिवादी के कब्जे में दे दिया गया है।

22. विद्वान वकील आगे तर्क देते हैं कि भले ही कोई अधिकार बचा हो, प्रत्यर्थी का दावा समय के साथ निराशाजनक रूप से बाधित हो गया

है। विद्वान वकील का तर्क है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अब दिनांकित समझौते पर वापस जाना होगा और पक्षों के बीच अधिकारों को तय करने के लिए उसी की व्याख्या करनी होगी जो सीमा के कानून के तहत संभव नहीं है। विद्वान वकील एक सरल परीक्षण का सुझाव देते हैं कि दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा स्पष्ट रूप से समय वर्जित होगा और इसलिए, प्रत्यर्थी के पास उस समझौते के संबंध में मध्यस्थता नहीं हो सकती है।

23. विद्वान वकील अंत में कहते हैं कि आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 11 (6), सीमा और अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जा सकता है, हालांकि, चूंकि विद्वान नामित न्यायाधीश ने उन मुद्दों का फैसला किया है, इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा इन प्रश्नों का फैसला करने का कोई सवाल ही नहीं होगा और इसलिए, अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता है।

24. श्री वेणुगोपाल, की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील तथापि, प्रत्यर्थी ने इंगित किया कि 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए अपीलार्थी के दायित्व के संबंध में विवाद। फीट। एफ. एस. आई. की मृत्यु कभी नहीं हुई थी क्योंकि अन्यथा प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित करने का कोई सवाल ही नहीं था 19.1.2005 पर देर से

समझौता ज्ञापन। वे बताते हैं कि अपीलार्थी ने एक रिट में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उस संपत्ति के संबंध में एक वचन दिया था

याचिका जो रिट याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और अपीलार्थी अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहा है उपक्रम। विद्वान वकील आगे बताते हैं कि सबसे पहले कोई श्री रैम मिल्स लिमिटेड नहीं था।

वी. UTILITY PREMISES (P) LTD. [वी. एस. सिरपुरकर, जे.] 287 86725 वर्ग किलोमीटर से परे शेष एफ. एस. आई. को सौंपने के लिए सहमत होकर। फीट। एक द्वारा दिनांकित समझौता 18.7.1994। यह केवल इस तथ्य के कारण था कि अपीलार्थी 1. 20 लाख वर्ग कि. मी. के हस्तांतरण के लिए दिनांकित 27.4.1994 समझौते से भी बंधे महसूस किया। फीट।

एफ. एस. आई. दिनांकित 27.4.1994 समझौते के तहत जिसके लिए उन्हें पूरा भुगतान प्राप्त हुआ था। रुपये का विचार। 21.60 करोड़। विद्वान वकील को इंगित करने के लिए दर्द हो रहा था

इसके अलावा कि वास्तव में यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि अपीलार्थी को लगभग 4 करोड़ रुपये अधिक मिले क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलार्थी कंपनी की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया था जो कि उसकी वित्तीय देनदारी थी। विद्वान वकील उस मुद्दे को 1.20 लाख

वर्ग किलोमीटर के बारे में बताते हैं। फीट। एफ. एस. आई. कभी भी बंद नहीं हुआ था और पार्टियों के बीच हमेशा जीवित था जिसने पार्टियों को अंततः 19.1.2005 दिनांकित समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने के लिए प्रेरित किया। विद्वान वकील तब बताते हैं कि प्रतिवादी ने बाद में यह महसूस करते हुए समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया था कि पूरी संपत्ति अपीलार्थी द्वारा 6.8.2004 पर गिरवी रखी गई थी जिसमें 4848.10 वर्ग मीटर की भूमि भी शामिल थी। फीट। जो दिनांकित 27.4.1994 समझौते का विषय था। इसलिए वह बताते हैं कि पक्षकार 1. 20 लाख वर्ग किलोमीटर के हस्तांतरण के लिए अपीलार्थी की ओर से दायित्व के संबंध में लगातार बातचीत की जा रही थी। फीट। एफ. एस. आई. और उस मुद्दे का कोई समाधान नहीं था। विद्वान वकील इंगित करते हैं कि जिस क्षण समझौता ज्ञापन रद्द कर दिया गया था, पक्षकार दिनांकित 27.4.1994 समझौते के तहत अपने अधिकारों पर वापस लौट आए और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी का दावा सही था।

संतुष्ट।

25. विद्वान वकील आगे बताते हैं कि चूंकि के तहत देनदारियाँ 27.4.1994 दिनांकित समझौते पर लगातार बातचीत की जा रही थी और इतनी सारी कार्यवाही में फिर से बातचीत की जा रही थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि सबसे पहले दोनों के बीच का मुद्दा पक्षकारों की मृत्यु हो

चुकी थी और दूसरी बात यह कि धारा 11 (6) के तहत आवेदन को समय से रोक दिया गया था। उस ओर से विद्वान वकील ने हरि शंकर सिंघानिया और अन्य मामलों में इस न्यायालय के कथित निर्णय पर भरोसा किया। वी. गौर हरि सिंघानिया और अन्य।, [2006] 4 एससीसी 658। विद्वान वकील द्वारा अंत में यह सुझाव दिया गया कि इस मुद्दे पर कि क्या कोई जीवित मुद्दा था या नहीं और सीमा का मुद्दा अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन मुद्दों को अंततः विद्वान न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आदेश पारित करते समय तय किया गया था। वह इंगित करता है कि यह केवल मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से है कि विद्वान नामित न्यायाधीश ने लाइव मुद्दे और सीमा के मुद्दे को संदर्भित किया है।

26. इन प्रतिद्वंद्वी विवादों पर यह देखना होगा कि क्या

विद्वान न्यायाधीश आदेश पारित करने में सही थे।

288 [2007] 4 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. हम अपीलार्थी द्वारा उठाए गए अंतिम विवाद पर विचार करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का दायरा। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि नामित न्यायाधीश पहले ही प्रत्यक्ष दावे के अस्तित्व के साथ-साथ सीमा के बारे में निष्कर्ष दे चुके हैं,

इसलिए निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण करना इस न्यायालय का काम होगा। इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष दावे और सीमा के संबंध में ऐसे मुद्दों का निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा अंततः नहीं बल्कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति के उद्देश्य से किया जाता है। हमारी राय में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश जो करते हैं वह एक मध्यस्थ की नियुक्ति करके मध्यस्थता कार्यवाही को गति देना है और यह उस उद्देश्य के लिए है कि निष्कर्ष के अस्तित्व के संबंध में दिया गया है

मध्यस्थता खंड, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, लाइव इश्यू और सीमा। यह विवादित नहीं हो सकता कि जब तक इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है, तब तक मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होगा। श्री साल्वे के साथ-साथ श्री वेणुगोपाल ने एस. बी. पी. एंड सी. ओ. में पैरा 39 में की गई टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्न., [2005] 8 एस. सी. सी. 618] जो निम्नानुसार हैंः

> " यह परिभाषित करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में क्या संपर्क किया था
>
> अदालत। उसे यह तय करना है कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है, जैसे कि अधिनियम में परिभाषित

और क्या वह व्यक्ति जिसने अनुरोध किया है उसके सामने, इस तरह के समझौते का एक पक्ष है। इंगित करना आवश्यक है कि वह इस सवाल का भी फैसला कर सकता है कि क्या दावा मृत था एक; या एक लंबे समय से वर्जित दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पक्षों ने लेन-देन को रिकॉर्ड करके समाप्त किया है उनके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि या प्राप्त करके बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान। यह उस स्तर पर संभव नहीं हो सकता है, यह तय करने के लिए कि क्या एक जीवित दावा किया गया है, वह है जो इसके भीतर आता है मध्यस्थता खंड की परिधि। इसे छोड़ना उचित होगा।

साक्ष्य लेने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न, मध्यस्थता में शामिल दावों के गुण-दोष के साथ। द. मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना है कि क्या आवेदक ने संतुष्ट किया है अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए शर्तें।

इन पहलुओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, प्रमुख न्याय या तो आगे बढ़ सकता है या ऐसा साक्ष्य दर्ज करवा सकता

है, जो हो सकता है आवश्यक है। हम सोचते हैं कि इस प्रक्रिया को अपनाने के संदर्भ में यह अधिनियम श्री रैम मिल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा।

UTILITY PREMISES (P) LTD. [वी. एस. सिरपुरकर, जे.] 289

बहुत अधिक के बिना मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य कार्यवाही के विभिन्न चरणों में अदालत से संपर्क करें मध्यस्थ न्यायाधिकरण "।

इस पैरा पर एक नज़र डालने से धारा 11 के तहत आदेश के दायरे का पता चलता है -

मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा पारित किया जाए। जहाँ तक क्षेत्रीय अधिकारिता और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से संबंधित मुद्दों का संबंध है, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को उन मुद्दों पर निर्णय लेना होता है यह जांचने के लिए कि क्या दावा एक मृत दावा है या इस अर्थ में कि क्या पक्षों ने पहले ही लेन-देन समाप्त कर लिया है और अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज की है या क्या संबंधित पक्षों ने वित्तीय दावों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की है। इसकी जांच करने में यदि पक्षों ने वित्तीय दावों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की

है, तो किसी भी मुद्दे के शेष रहने का कोई सवाल ही नहीं होगा। यह इस मायने में है कि मुख्य न्यायाधीश को इस बात की जांच करनी है कि क्या उनके अवशेष कुछ भी हैं। समझौते के संबंध में पक्षों के बीच निर्णय लिया गया और क्या पक्ष अभी भी ऐसे किसी मामले पर मुद्दे पर हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश, सख्त अर्थों में, मुद्दे का निर्णय नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में यह उनके लिए है कि वे इस तरह के मुद्दे का पता लगाएं और अपना संतोष दर्ज करें कि ऐसा मुद्दा पक्षों के बीच मौजूद है।

यह केवल उस अर्थ में है कि एक जीवित मुद्दे पर निष्कर्ष दिया जाता है। यहां तक कि दोहराव की कीमत पर भी हमें यह कहना चाहिए कि यह केवल यह पता लगाने के उद्देश्य से है कि क्या मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की जानी है कि मुख्य न्यायाधीश को संतोष दर्ज करना है कि वे पक्षों के बीच एक जीवित मुद्दा बने हुए हैं। यही बात सीमा के बारे में है जो हमेशा कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल है। मुख्य न्यायाधीश को केवल अपनी संतुष्टि दर्ज करनी है कि प्रथम दृष्टया यह मुद्दा समय बीतने तक मृत नहीं हुआ है या इस मामले में कोई पक्षकार नहीं है।

समझौते में शामिल मुद्दों को उठाने के लिए कानून द्वारा अनुमत समय से परे अपने अधिकारों पर समझौता नहीं किया गया है। यही कारण है कि उपरोक्त पैरा में यह बताया गया था कि कभी-कभी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले प्रत्यक्ष दावे के संबंध में प्रश्न को

छोड़ना उचित होगा। उसे बस इतना करना है कि अपनी संतुष्टि दर्ज करनी है जो पार्टियों के पास नहीं है उनके अधिकारों को बंद कर दिया और मामले को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया गया है। इस प्रकार, जहां मुख्य न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक जीवित मुद्दा मौजूद है, तो स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष में यह निष्कर्ष शामिल होगा कि पक्षों के संबंधित दावे सीमितता से बाधित नहीं हुए हैं।

[2007] 4 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 290

28. वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह देखा जाएगा कि नामित न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि पक्षों ने अपने दावों को पूरा नहीं किया था। हमें, इस स्तर पर, ध्यान देना चाहिए कि पहले समझौते के बाद जो स्पष्ट रूप से 1,20,000 sq के संबंध में मुद्दे को शामिल करता है। फीट। एफ. एस. आई. का उक्त मुद्दा दलों को बार-बार परेशान करता रहा। हम पहले ही समझौतों और उनके रद्द होने का उल्लेख कर चुके हैं। पहला समझौता 27.4.1994 पर था जो मूल समझौता है। इसके बाद पक्षों ने एक दूसरा समझौता किया जो इस तथ्य के कारण आवश्यक था कि तब अपीलार्थी केवल 86725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध करा सकता था। फीट। एफ. एस. आई. यह इस समझौते के तहत था कि अपीलार्थी आगे की भूमि के लिए सहमत हुआ। इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर है। एमटीआरएस। उत्तरदाताओं द्वारा विकसित करने की अनुमति

दी जाएगी कि कौन सी भूमि बॉम्बे नगर निगम द्वारा नगर प्राथमिक विद्यालय और खेल के मैदान के लिए आरक्षित थी। उस समझौते के अनुसार, अपीलार्थी ने उक्त आरक्षण को किसी अन्य संपत्ति में स्थानांतरित करने का बीड़ा उठाया। इस समझौते के बाद 9.11.1994 दिनांकित एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें एक तीसरा पक्ष, अर्थात् भूपेंद्र कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड शामिल हुआ। 22.6.1996 पर 18.7.1994 दिनांकित समझौते को आपसी सहमति से रद्द कर दिया गया था क्योंकि पक्ष आरक्षण को आगे स्थानांतरित करने की लागत के बारे में सहमत होने में असमर्थ थे, जिससे तीसरे पक्ष, अर्थात्, भूपेंद्र कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड को बाहर कर दिया गया था। अगर चीजें इस स्तर पर बनी हुई थीं, तो 1,20,000 वर्ग के संबंध में मुद्दे का कोई सवाल ही नहीं था। फीट। एफ. एस. आई. का जीवित रहना। हालाँकि, इसके बाद के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा पक्षों के बीच जलता रहा जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने 2500 वर्ग किलोमीटर के संबंध में 4.5.2001 पर अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया था। एमटीआरएस। स्पष्ट रूप से 1,20,000 वर्ग के संबंध में उनके हितों की रक्षा के लिए। फीट। एफ. एस. आई. यह स्पष्ट है कि इस एफ. एस. आई. को उपरोक्त 2500 वर्ग मीटर भूमि से जोड़ा गया था। एम. टी. आर. एस. यद्यपि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 9 के तहत निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अपने प्रयास में विफल रहे, लेकिन उन्होंने चीजों को उस पर नहीं छोड़ा

और इस तरह के मुद्दे को पहले मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए 11.6.2002 दिनांकित नोटिस देकर और दूसरा दिल्ली के समक्ष दायर अपनी रिट याचिका में इस मुद्दे को शामिल करके लाया। उच्च न्यायालय, जिसमें अपीलकर्ताओं को यह वचन देने के लिए कहा गया था कि वे उस संपत्ति को नहीं बेचेंगे जो दिनांकित 27.4.1994 के समझौते के तहत शामिल थी, जिसमें स्पष्ट रूप से 1,20,000 वर्ग शामिल था। फीट। एफ. एस. आई. यह उपक्रम अब भी जारी है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता या अन्यथा में जाना हमारे लिए उचित नहीं है। उपक्रम करना क्योंकि यह हमारे सामने लंबित प्रश्न नहीं है, हालाँकि, यह केवल यह दर्शाता है कि पक्षों ने 1,20,000 वर्ग के संबंध में प्रश्न को बंद नहीं किया था। फीट। एफ. एस. आई. मानो यह सब पर्याप्त नहीं था, अंत में पक्ष एक समझौता ज्ञापन के लिए 19.1.2005 पर सहमत हुए जहां यह सटीक प्रश्न सामने आया। वहाँ, ऐसा लगता है कि प्रतिवादी 1,20,000 वर्ग के संबंध में अपना दावा छोड़ने के लिए सहमत हो गया था। फीट। एफ. एस. आई. श्री रैम मिल्स लिमिटेड। 1 '. UTILITY PREMISES (P) LTD. [वी. एस. सिरपुरकर, जे.] 291

हालांकि, ऐसा लगता है कि प्रतिवादी समझौता ज्ञापन से बाहर हो गया और रद्द कर दिया।

इसने मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता नोटिस देने का फैसला किया।

29. विद्वान वकील श्री साल्वे बताते हैं कि यह संभव नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी समझौता ज्ञापन में की गई प्रतिबद्धता से बाहर नहीं निकल सका और एकपक्षीय रूप से समझौता ज्ञापन को रद्द नहीं कर सकता था जैसा कि प्रतिवादी ने किया था रुपये के विचार के लिए अपने दावे को छोड़ने के लिए स्वीकार किया। 1. 20 करोड़ और उसी में से 1 लाख का आंशिक भुगतान स्वीकार किया था। हमे यहाँ बताना चाहिए कि यह निर्णय लेना हमारे लिए नहीं होगा कि क्या उत्तरदाता समझौता ज्ञापन को अस्वीकार करने और मध्यस्थता की सूचना देने के अपने अधिकारों के भीतर थे। 19.1.2005 दिनांकित समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के कारण पक्षों के क्या अधिकार होंगे, यह हमें इस अधिकार क्षेत्र में बैठकर तय नहीं करना होगा। हमारे पास है।

केवल यह निर्णय लेने के लिए कि क्या वर्तमान मुद्दे के संबंध में पक्ष अभी भी आमने-सामने थे। समझौता ज्ञापन के लिए उनकी ओर से महसूस की गई आवश्यकता से पता चलता है कि यह मुद्दा बंद नहीं हुआ था। श्री साल्वे का तर्क है कि उत्तरदाताओं को अब 27.4.1994 दिनांकित समझौते पर वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब उन्होंने 19.1.2005 दिनांकित समझौता ज्ञापन में प्रवेश करके मुद्दे को बंद करने

का विकल्प चुना था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने उस पर हमारा निष्कर्ष मांगा। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह निष्कर्ष देना हमारा काम नहीं होगा। हमारी राय में यह तथ्य कि पार्टियों ने दिनांकित 19.1.2005 एमओयू बनाने का विकल्प चुना, यह बताता है कि 1,20,000 वर्ग मीटर के संबंध में आदेश। फीट। एफ. एस. आई. को कभी भी बंद नहीं किया गया था या कम से कम कभी भी बंद नहीं माना गया था और इस मायने में यह अभी भी एक जीवित मुद्दा था। विद्वान वकील श्री सावले ने नथानी स्टील्स के निर्णय पर भरोसा किया

लिमिटेड वी. एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शंस, [1995] सप। 3 एससीसी 324। हमारा ध्यान विशेष रूप से पैराग्राफ 3 की सामग्री की ओर आकर्षित किया गया था जो इस प्रकार हैः

> "..... एक बार जब किसी विशेष संबंध में पूर्ण और अंतिम समझौता हो जाता है के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में विवाद या अंतर अनुबंध में मध्यस्थता खंड और वह विवाद या अंतर है अंत में पक्षों द्वारा और उनके बीच इस तरह के विवाद या मतभेद का निपटारा किया जाता है।
>
> मध्यस्थता विवाद और मध्यस्थता खंड नहीं रहता है कुछ अन्य मामलों के लिए भी लागू नहीं किया जा सकता

है, अनुबंध निर्वाह में हो सकता है। एक बार जब पक्ष एक समझौते पर पहुंच जाते हैं किसी अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या मतभेद के संबंध में और उस विवाद या मतभेद को अंतिम रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। पक्षों द्वारा और उनके बीच समझौता, जब तक कि वह समझौता निर्धारित न हो उचित कार्यवाहियों में एक तरफ, यह किसी एक के मुंह में नहीं हो सकता है समझौते के पक्षकारों ने इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह एक गलती करें और मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए आगे बढ़ें। यदि अनुबंध की पवित्रता की अनुमति दी जाती है, तो समझौता भी एक अनुबंध होने के नाते 292 होगा।

[2007] 4 एस सी आर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पूरी तरह से खो दिया जाएगा और यह एक पक्ष के लिए लाभ लेने के लिए खुला होगा समझौते के तहत और फिर उसी आधार पर सवाल करना समझौते को अलग रखे बिना गलती "

यद्यपि प्रथम आक्षेप पर टिप्पणियाँ अपीलार्थियों के पक्ष में प्रतीत होती हैं, लेकिन करीब से देखने पर वे ऐसी नहीं हैं। यह एक ऐसा मामला

था जिसमें एक अनुबंध में पक्षों ने अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया था और पक्षों ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया था कि वे इस तरह के समझौते पर पहुंचे हैं। उन परिस्थितियों में ही अवलोकन किए गए थे। हालाँकि, हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि इस मुद्दे के संबंध में पक्षों के बीच एक पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ था। फीट। एफ. एस. आई. और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जहां प्रतिवादी और भूपेंद्र कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड जो तीसरे समझौते के पक्षकार थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास 86,725 वर्ग किलोमीटर तक के अधिकार रह गए थे। फीट। एफ. एस. आई. यह देखा जाना चाहिए कि 1,20,000 वर्ग के संबंध में किसी भी विचार का कोई संदर्भ नहीं है। फीट। एफ. एस. आई. का, रुपये के आंकड़े से बहुत कम। इस समझौता ज्ञापन में 1.2 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस बारे में कि इस समझौता ज्ञापन का प्रतिवादी के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं किया गया था। नथानी के मामले (ऊपर) में इस मुद्दे को स्वीकार किया गया था और उस पर पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया था। यहाँ पक्षकार और विशेष रूप से उत्तरदाता इस बात पर गंभीरता से विवाद कर रहे हैं कि 1,20,000 वर्ग के बारे में मुद्दा। फीट। एफ. एस. आई. का मामला अंततः पक्षों के बीच सुलझा लिया गया। यह केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए होगा कि वह प्रतिवादी के

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रभाव का निर्णय करे। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समझौता ज्ञापन को अनुबंध की प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। नथानी के मामले में समझौते को एक अनुबंध के रूप में देखा गया था और इसलिए, यह दोहराया गया था कि यदि पक्षों को अनुबंध से अपने दायित्व से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, तो समझौते को कोई पवित्रता नहीं दी जाएगी जो एक अनुबंध की प्रकृति में हैं। यही कारण है कि, हमारी राय में, नथानी के मामले में निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हम इस मोड़ पर यह भी दोहराते हैं कि बादल 2500 वर्ग किलोमीटर पर हैं। एमटीआरएस। ऐसी भूमि जो स्पष्ट रूप से एफ. एस. आई. से जुड़ी हुई है 1,20,000 स्क्वायर। फीट। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन द्वारा बनाया गया वचन अभी भी व्यापक है और समझौता ज्ञापन की तारीख तक भी बना हुआ है। यही कारण है कि हमारी स्पष्ट राय है कि 1,20,000 वर्ग के संबंध में मुद्दे का कोई अंतिम समाधान नहीं हुआ था। फीट। एफ. एस. आई. का दिनांक 19.1.2005 के समझौता ज्ञापन द्वारा भी। यदि ऐसा था, तो यह स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लाइव मुद्दा था और पार्टियों के बीच उस मुद्दे पर लॉगरहेड्स थे।

30. एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि विद्वान नामित न्यायाधीश का यह मानना सही था कि एक लाइव मुद्दा था, श्री रैम मिल्स लिमिटेड का सवाल।

प्रत्यक्ष रूप से या पत्राचार के माध्यम से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप सीमा की घड़ी टिक टिक करना शुरू नहीं करती है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> " जहां सुलह के साथ या उसके बिना समझौता संभव नहीं है, तो मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय का चरण आता है। अनुच्छेद 137 के अनुसार इस अर्थ में समझा जाता है, तब तक जब तक पक्ष बातचीत में हैं और यहां तक कि मतभेद भी सामने आ गए होंगे, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 137 के तहत एक सीमा शुरू हो गई है। इस तरह की व्याख्या पक्षकारों को मुकदमेबाजी/मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर करेगा, यहां तक कि जहां भी पार्टियों के स्वयं मुद्दों को हल करने की गंभीर उम्मीद है।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने, हमारे विचार में गलती की है अपीलार्थियों की अपील को खारिज करना और उनके निष्कर्षों की पुष्टि करना एकल न्यायाधीश इस प्रभाव के लिए कि द्वारा किया गया आवेदन अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत अपीलकर्ता एक संदर्भ के लिए पूछ रहे हैं सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत समय से परे था।

ध्यान दिया, वास्तव में पक्षों के बीच पत्राचार, बाहर निकलता है कि इसका पालन करने और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा था पक्षों के बीच समझौते में पारस्परिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

इन टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बातचीत कहाँ हुई थी। फिर भी, सीमा अवधि शुरू करने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

31. श्री साल्वे के अनुसार, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील अपीलकर्ताओं ने दिनांकित समझौते के संबंध में उत्तरदाताओं के खिलाफ घड़ी की टिक टिक करना शुरू कर दिया था और उनके पास सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार मुकदमा दायर करने के लिए केवल तीन साल की अवधि हो सकती थी और इस तरह उस समझौते के संदर्भ में किया गया दावा अब वर्ष 2005 में मध्यस्थ नहीं हो सकता है। हम सहमत नहीं हैं। यही कारण है कि हमने दोनों पक्षों के बीच बातचीत का पूरा इतिहास दिया है। ऐसा लगता है कि चीजें 19.1.2005 द्वारा भी तय नहीं हुई हैं, लेकिन यह इसके लिए होगा मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेगा। हम इस स्तर पर केवल यह देखते हैं कि प्रतिवादी के दावे को पहले समझौते के कारण या सीमा समाप्त होने के कारण मृत नहीं कहा जा सकता है। 19.1.2005 दिनांकित समझौता ज्ञापन का क्या प्रभाव है; क्या प्रतिवादी ने उक्त समझौता ज्ञापन को अस्वीकार करने में उचित ठहराया

था; और क्या पहले के दिनांकित 27.4.1994 समझौते पर इसके खंडन का प्रभाव मध्यस्थ न्यायाधिकरण को तय करना होगा। ग्रुप चिमिक ट्यूनीशियन एस. ए. बनाम। दक्षिणी पेट्रोकेमिकल उद्योग निगम। लिमिटेड, [2006] 5 एस. सी. सी. 275 यह न्यायालय ने पैरा 10 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों में भी जा सकता है।

294 इस विषय पर चर्चा के बीच के दावों के लिए सीमा का प्रश्न केवल यह मानने के लिए है कि चूंकि मुद्दा अभी भी जीवित है, इसलिए यह मानते हुए ए को दबाने का कोई सवाल ही नहीं होगा कि मुद्दा सीमित रूप से मृत हो गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर भी सीमा का प्रश्न

32. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं कि नामित न्यायाधीश की नियुक्ति सही थी इसलिए, हम अधिनियम की धारा 11 (6) में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

बी. एस

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जितेन्द्र गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।